जयपुर • कोटा • बीकानेर • उदयपुर • अजमेर • जालोर • हिण्डौनसिटी • चूरू

राष्ट्रदूत

epaper.rashtradoot.com

अजमेर

Rashtradoot

फोनः- 2627612, 2427249 फैक्सः- 0145-2624665 वर्षः 29 संख्याः 212 प्रभात अजमेर, रविवार 2 मार्च, 2025 आर.जे./ए.जे./73/2015-2017 पृष्ठ 6 मूल्य 2.50 रु.

ज़ैलेंस्की व ट्रम्प के बीच वाइट हाउस में, अमेरिका के राष्ट्रपति के दफ्तर में हुई झड़प

इस झड़प ने पर्दा उठा दिया, उस किंवदंती पर से कि अमेरिका का राष्ट्रपति विश्व का सबसे सशक्त व्यक्ति है

-अंजन रॉय-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 1 मार्च। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ैलेंस्की और अमेरिकी राष्ट्रपति के बीच ओवल ऑफिस में हुई खुली झड़प ने इस मिथक से पर्दा उठा दिया है कि अमेरिका का राष्ट्रपति विश्व का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति है। यह घटना आधुनिक समय के कूटनीतिक इतिहास में अप्रत्याशित थी।

कमजोर, और अपने शक्तिशाली पड़ोसी के साथ निरंतर युद्ध से घायल, यूक्रेन के राष्ट्रपति ने खुद को साहसी व दृढ़ व्यक्तित्व वाले नायक के रूप में दर्शाया। उन्होंने, सबसे शक्तिशाली आदमी द्वारा अपने ही गढ़ में की जा रही दादागिरी का बेधड़क सामना किया और बिना डरे, डटे रहे। संदेश यह था: जब आप बिल्कुल कोने में धकेल दिए जाते हैं, तो आप अमेरिकी राष्ट्रपति से उनके अपने दफ्तर में भी मुकाबला कर सकते हैं।

उनके प्रतिद्वंद्वी, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प रूसियों की एक कठपुतली और रूस की प्रतिक्रिया के संभावित परिणामों से डरने वाले एक कायर के रूप में सामने आए हैं। उनके उपराष्ट्रपति की स्थिति इससे भी बदतर है, वे तो ट्रम्प के हाथ का खिलौना मात्र हैं।

सीधे शब्दों में कहें, तो अमेरिका ने एक फायदेवाला सौदा खो दिया है। यूक्रेन के दुर्लभ खनिजों को डवलप करना और शेयर करना अमेरिका के उद्योगों और रक्षा क्षेत्र के लिए एक भारी एग्रीमैंट है। ऐसा लग रहा है कि अमेरिका को एक बार फिर इन खनिजों को सुरक्षित करने के लिए बातचीत शुरू करनी पड़ेगी।

यदि सतह पर देखा जाए, तो यूक्रेन ने रूस की आक्रामकता के खिलाफ अपनी लड़ाई में अमेरिकी समर्थन खो दिया है, लेकिन, दूसरी तरफ, रूस के राष्ट्रपति और तानाशाह, व्लादिमिर पुतिन के सामने झुकना अमेरिका के राष्ट्रपति के लिए और भी अधिक कठिन काम होगा।

रूस के लोगों ने जहाँ अपने सबसे जुझारू प्रतिद्वंद्वी की स्पष्ट अपमानजनक हार का जश्न मनाया होगा, वहीं, उन्हें यह समझना चाहिए कि जल्द ही उन्हें एक और भी अधिक दुष्कर समस्या का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि अपनी साख साबित करने के लिए अब अमेरिका, रूस की पूरी तरह से अधीनता नहीं कर पाएगा।

अमेरिकी राष्ट्रपति और उनके सहयोगियों के व्यवहार ने पूरे पश्चिमी यूरोप को यूक्रेन का खुले तौर पर समर्थन करने के लिए बाध्य किया था। यहां तक कि इटली की प्रधानमंत्री, ज्योर्जिया मेलोनी, जो यूक्रेन को समर्थन देने को लेकर खास उत्साहित नहीं थीं, ने भी अपना रुख बदल लिया।

अब पूरा यूरोप यूक्रेन का समर्थन करने और उसके पीछे खड़ा होने के लिए एकजुट हो रहा है, जबकि, अब तक इस मुद्दे पर यूरोप बंटा हुआ था। तथापि, अभी भी कुछ अपवाद हो सकते हैं, जैसे हंगरी, जो हाल तक यूक्रेन का समर्थन करने के खिलाफ था। हालांकि, ऐसे देशों की आवाज़, अन्य देशों द्वारा अमेरिका के रूख की सख्त आलोचना और यूक्रेन के समर्थन की आवाज़ में दब जाएगी।

यह होना तय था। चुनाव में अपनी पुन: जीत के बाद से, डॉनल्ड ट्रंप अधिक से अधिक घमंडी होते जा रहे थे। फ्रांस के राष्ट्रपति, इमैनुएल मैक्रों के साथ अपनी संयुक्त प्रैस कॉन्फ्रैंस में, डॉनल्ड

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

- इस झड़प ने यह भी साबित कर दिया कि अमेरिका का राष्ट्रपति, रूस की सरकार की कठपुतली है तथा इस भय से ग्रसित है कि रूस का विरोध करने का क्या परिणाम हो सकते हैं।
- इस झड़प ने यह भी दिखा दिया, अमेरिका के उपराष्ट्रपति भी, राष्ट्रपति ट्रम्प के मनपसंद खिलौने से ज्यादा महत्व नहीं रखते। हालांकि, प्रथत दृष्टया ऐसा लगता है कि यूक्रेन कमज़ोर हुआ है, पर, अमेरिका की भी कठिनाईयां बढ़ी हैं। अब अमेरिका खुलकर रूस का पक्ष लेने में कुछ हिचकिचायेगा तथा यूक्रेन से औद्योगिक दृष्टि से महत्वपूर्ण खनिजों को प्राप्त करने में इसे भारी जोर आयेगा।
- यूक्रेन को एक और फायदा यह हुआ कि पूरा यूरोप अब यूक्रेन के समर्थन में खड़ा हो गया है। जबकि, पहले यूक्रेन का साथ देने के प्रश्न पर यूरोप विभाजित सा था, एकमत नहीं था।

चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के बकाया वेतन पर हाई कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया

जयपुर, 1 मार्च। राजस्थान हाईकोर्ट ने महुआ नगर पालिका के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का पन्द्रह महीने का बकाया वेतन 15 दिन में देने के आदेश दिए हैं। ऐसा नहीं करने पर अदालत ने पंचायती राज आयुक्त, स्थानीय निकाय निदेशक और नगर पालिका के कार्यकारी अधिकारी का वेतन रोकने को कहा है। अदालत ने यह भी कहा कि यदि प्रमुख स्वायत्त शासन सचिव आदेश की पालना में फेल हुए तो मुख्य सचिव को निर्देश दिए जाते हैं कि वे प्रमुख स्वायत्त शासन सचिव का वेतन रोक लें। जस्टिस अनूप कुमार ढंड की एकलपीठ ने यह आदेश संतराम शर्मा की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए।

याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता केपी सिंह ने कहा कि अदालत ने गत 18 फरवरी को राज्य सरकार को आखिरी मौका देते हुए पूछा था कि याचिकाकर्ता का बकाया वेतन क्यों रोका गया है। इस पर सरकारी वकील ने इस संबंध में दिशा-निर्देश प्राप्त

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

- आदेश में 15 माह का बकाया वेतन 15 दिन में नहीं देने पर पंचायती राज आयुक्त, स्थानीय निकाय निदेशक व महवा नगर पालिका के कर्मचारी अधिकारी का वेतन रोकने के निर्देश दिये गये हैं।

कर्नाटक के मु.मंत्री सिद्धारमैया ने केन्द्रीय सरकार के खिलाफ सड़क पर उतरने की धमकी दी

सिद्धारमैया के अनुसार, केन्द्रीय सरकार कर्नाटक का हिस्सा 41 प्रतिशत से घटाकर 40 प्रतिशत करने की तैयारी में है, वित्त आयोग की मदद से

-लक्ष्मण वैंकट कुची-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 1 मार्च। कर्नाटक के मुख्यमंत्री एस. सिद्धारमैया भी केन्द्र सरकार और उसके विभिन्न कथित "राज्य-विरोधी" निर्णयों के खिलाफ आक्रामक हो गये हैं। उन्होंने परिसीमन की कवायद पर कड़ा प्रहार करते हुये कहा कि इसे दक्षिण भारतीय राज्यों पर थोपा जा रहा है। शनिवार को मुख्यमंत्री ने "एक्स" पर डाली अपनी सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि केन्द्र सरकार का रुख राज्य-विरोधी है तथा उसके निर्णय टैक्सों और विकास फंड्स के मामलों में कर्नाटक को उसके वाजिब हिस्से से वंचित कर रहे हैं। अगर ऐसा हुआ तो वे राज्य की जनता के अधिकारों की खातिर लड़ाई के लिए सड़कों पर उतर आयेंगे।

सिद्धारमैया ने टैक्स रेवन्यू के कर्नाटक के आधिकारिक हिस्से को और भी कम करने की केन्द्र सरकार की कोशिशों की कड़ी आलोचना की और कहा, "अगर अपील और बातचीत निष्फल रहती हैं तो हम सड़कों पर उतरने तथा लोगों के साथ आकर लड़ने में नहीं हिचकेंगे।

मुख्यमंत्री ने कहा, "यह केवल कर्नाटक विरोधी ही नहीं, बल्कि संविधान में प्रतिष्ठापित (देश के) संघीय ढाँचे पर भी सीधा हमला है।" उन्होंने कुछ रिपोर्टों का हवाला दिया, जो यह संकेत देती हैं कि केन्द्र सरकार, वित्त आयोग के माध्यम से, कर्नाटक के हिस्से को 41 प्रतिशत से 40 प्रतिशत करने की सिफारिश कराने की तैयारी कर रही है।

सिद्धारमैया ने आरोप लगाया, "जब से नरेन्द्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं, केन्द्र की नीतियाँ राज्यों के संवैधानिक अधिकारों में लगातार कटौती करती आ रही हैं तथा उन्हें कमज़ोर करती आ रही हैं।"

सिद्धारमैया ने केन्द्र की इन कोशिशों में परिसीमन की कवायद को भी जोड़ दिया तथा दक्षिण भारत में लोकसभा सदस्यों की संख्या कम करने के केन्द्र सरकार के प्रयासों की भर्त्सना की। उन्होंने केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह के इन दावों को विश्वास के योग्य नहीं माना कि परिसीमन में दक्षिण भारत के किसी भी राज्य की एक भी सीट कम नहीं होगी।

सिद्धारमैया ने कहा कि दक्षिण भारत की सीटें तो कम होंगी ही, इसके साथ ही, उत्तरी भारत की सीटों में बड़ी मात्रा में वृद्धि भी होगी। इस प्रकार, उत्तरी भारत लोकसभा में तथा इसके फलस्वरूप, केन्द्र सरकार के निर्माण में ज्यादा ताकतवर हो जायेगा।

- सिद्धारमैया की यह शिकायत है कि "डीलिमिटेशन" से केन्द्रीय सरकार दक्षिण भारत के राज्यों की सीटें व राजनीतिक प्रभाव कम करेगी।
- अगर, केन्द्रीय सरकार ने अपना रवैया नहीं बदला तो, कर्नाटक के हितों की रक्षा के लिए, मु.मंत्री स्वयं सड़क पर उतरेंगे।

प्र.मंत्री ने सूफी मुसलमानों की तरफ मित्रता का हाथ बढ़ाया

-श्रीनन्द झा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 1 मार्च। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी तथा भाजपा ने, पसमन्दाओं के बाद, अब सूफी मुस्लिमों तक पहुँच बनाने की योजना शुरू कर दी है। इस प्रयास का उद्देश्य भाजपा को इस रूप में स्थापित करना है कि यह पार्टी भारत के सभी वर्गों और समुदायों का प्रतिनिधित्व करती है।

नरेन्द्र मोदी सरकार के 11 वर्षों में, भाजपा ने स्वयं को बहुसंख्यक हिन्दू समुदाय का प्रतिनिधित्व करने वाली पार्टी के रूप में तो प्रस्तुत किया ही है, लेकिन इसके साथ ही, उसने स्वयं को मुस्लिमों सहित, अन्य समुदायों तक पहुंच रखने वाली पार्टी के रूप में भी पेश किया है। तीन तलाक जैसे निर्णयों के जरिये, भाजपा मुस्लिम महिलाओं को प्रभावित करने की कोशिश करती रही है। पसमन्दा मुस्लिमों के पक्ष में अभियान चला कर, पार्टी ने दो उद्देश्यों की पूर्ति की कोशिश की है- पहला, अभिजात्य मुस्लिमों और दलित पसमन्दाओं के बीच एक पाला खींचना, और दूसरा, यह विचार देना कि जाति व्यवस्था केवल हिन्दू समाज में ही नहीं है।

शुक्रवार को दिल्ली में "जहाने-खुसरो" के 25वें संस्करण को सम्बोधित करते हुये प्रधानमंत्री मोदी ने सूफी परम्परा की जबरदस्त तारीफ की। इस अवसर पर बोलते हुये उन्होंने तेरहवीं शताब्दी के कवि और संगीतज्ञ अमीर खुसरो के व्यक्तित्व और कृतित्व की भूरि-भूरि प्रशंसा की। प्रधानमंत्री ने सूफियों की बहुलवादी परम्पराओं का विशेष रूप से जिक्र किया तथा कहा कि जहाँ वे इस्लाम के अनुयायी थे, वहीं, सूफी सन्त हिन्दू देवी-देवताओं, जैसे भगवान कृष्ण, के प्रति अपूर्व श्रद्धा रखते थे। उन्होंने याद दिलाया कि जब वे गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने अहमदाबाद की एक सूफी मस्जिद एवं मकबरा परिसर का किस तरह से पुनरोद्धार कराया था।

उन्होंने कहा कि सूफी सन्त पवित्र कुरान तो पढ़ते ही थे, वे वेदों को भी सुनते थे। उन्होंने कहा, यह "वसुधैव कुटुम्बकम्" जैसी बात ही तो है।"

भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी ने कहा, "सूफीवाद भारतीय संस्कृति का हिस्सा है तथा यह मतान्धता का सामना तथा शान्ति को प्रोत्साहित कर सकता है। सूफीवाद का उद्देश्य मानव और ईश्वर के बीच सीधा सम्पर्क कायम करना है। ईश्वर, अल्लाह, राम, कृष्ण, ईसा या वाहे गुरू के विभिन्न रूपों में पूज्य है।"

भाजपा का सूफी-सम्पर्क 2024 के संसदीय चुनावों से पहले ही शुरू हो

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

- तेरहवीं शताब्दी के जाने-माने सूफी कवि व संगीतकार अमीर खुसरो की स्मृति में मनाये जा रहे, जहान-ए-खुसरो प्रोग्राम में मोदी ने अपनी अभिभाषण में यह जताया कि सूफी दर्शन काफी कुछ "वसुधैव कुटुम्बकम् सिद्धांत" पर आधारित है।

समय पर फ्लैट नहीं देने पर 5.20 लाख रूपए का हर्जाना

जयपुर, 1 मार्च। जिला उपभोक्ता आयोग, द्वितीय ने तय समय में फ्लैट का कब्जा नहीं देने पर बिल्डर मैसर्स सिद्धा इंफ्रा प्रोजेक्ट प्रा.लि. व अन्य पर 5.20 लाख रुपए का हर्जाना लगाया है। इसके साथ ही, आयोग ने परिवादी की ओर से जमा कराई गई राशि सहित, कुल 36.58 लाख रुपए की राशि नौ फीसदी ब्याज सहित लौटाने को कहा है। आयोग के अध्यक्ष ग्यारसी लाल मीणा और सदस्य हेमलता अग्रवाल ने यह आदेश पवन चौपड़ा व अन्य के परिवाद पर दिए।

परिवाद में कहा गया कि परिवादी ने बिल्डर सिद्धा इन्फ्रा प्रोजेक्टस प्रा. लि. के अजमेर रोड़ स्थित प्रोजेक्ट सिद्धा आंगन फेज़-2 में बन रहे आवासीय अपार्टमेंट मयूर योजना में एक फ्लैट खरीदा था। उसने बिल्डर के साथ 17 सितम्बर, 2018 को एक करार किया

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

- जिला उपभोक्ता आयोग द्वितीय ने सिद्धा इंफ्रा प्रोजैक्ट्स प्रा. लि. पर यह हर्जाना लगाया।

'आप इस स्थिति में नहीं हैं कि हमें निर्देश दे सकें'

ट्रम्प ने धमकाते हुए ज़ैलेंस्की से कहा, और इसके थोड़ी देर बाद यूक्रेन के प्रतिनिधि मंडल को वाइट हाउस से जाने के लिए कहा गया तथा राष्ट्रपति ट्रम्प का भोज अछूता धरा का धरा रह गया

-डॉ. सतीश मिश्रा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 1 मार्च। यू.एस. प्रैसिडैंट -डॉनल्ड ट्रंप और उनके यूक्रेनी समकक्ष वोलोडिमीर ज़ैलैंस्की के बीच झड़प ऐसी घटना है, जिस पर दंतकथाएं बना करती हैं।

कई लोग जहाँ इसे यूक्रेनियन प्रैसिडैंट का मूर्खतापूर्ण व्यवहार मानेंगे, वहीं, ज़ैलैंस्की के देश के लोग इसे बहादुरी मानेंगे। इसका एक उदाहरण भारत में मिल सकता है महाराणा राणा प्रताप द्वारा मुगलों की शक्ति के खिलाफ खड़ा होना। "जिसकी लाठी उसकी भैंस" यह उक्ति सदा सही नहीं होती। शक्तिशाली के आगे नहीं झुकना या डेविड और गोलायथ की कहानी, कुछ ऐसी समानताएं व उदाहरण हैं, जो रुस के साथ युद्ध कर रहे ज़ैलैंस्की के देश में दी जाएंगी।

दोनों के बीच मीटिंग की शुरुआत मुस्कुराहट और हाथ मिलाने से हुई, पर मीटिंग कुछ ही मिनटों में झड़प में बदल गई, वो भी विश्व के मीडिया के सामने, जो वाइट हाउस में मौजूद था। यहां मीटिंग और उन शब्दों की एक झलक प्रस्तुत है, जो आम आदमी को घटना की वास्तविक तस्वीर उपलब्ध करा सकती हैं।

ट्रम्प ने ऊँची आवाज में ज़ैलैंस्की से कहा, आप इस स्थिति में नहीं हैं कि हमें निर्देश दे सकें। इसके बाद यूक्रेन का डैलिगेशन वाइट हाउस से चला गया।

मीटिंग सही ट्रैक पर थी, अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वैंस ने इसे उकसाया। उन्होंने रुस -यूक्रेन वॉर के समाधान के लिए कूटनीति की आवश्यकता पर जोर दिया। वैंस ने पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडन की आलोचना की।

एक पत्रकार के सवाल का जवाब देते हुए वैंस ने कहा, हमने जो बाइडन के रास्ते पर चलने की कोशिश की, छाती ठोक कर यह बताने का प्रयास किया कि अमेरिका के राष्ट्रपति के शब्द अमेरिका

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

- वाइट हाउस में, अमेरिका के राष्ट्रपति के दफ्तर में, दोनों देशों के राष्ट्रपतियों के बीच बातचीत ठीक-ठाक चल रही थी, पर, उपराष्ट्रपति जे.डी. वैंस ने बीच में पूर्व राष्ट्रपति बाइडन को कोसना शुरु कर दिया और बातचीत की लय बदल सी गई और फिर स्थिति को कोई संभाल नहीं पाया।